कांग्रेस ने अव्यवहारिक व्यवस्था कर बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था : मदन राठौड़

कांग्रेस ने अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर लूट-पाट के दरवाजे खोले : मदन दिलावर

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर बनाई गई समीक्षा कमेटी पर गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र में अप्रासांगिक व्यवस्था कर बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन भाजपा सरकार कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था की जांच करवाकर हमारे बच्चों का बेस तैयार करने का काम करेगी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में केवल वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दी। लेकिन इन स्कूलों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की और ना ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की। कांग्रेस ने दूर दराज के गांवों में चल रही हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर अंग्रेजी में कर दिया जो कांग्रेस का अव्यवहारिक फैसला था। कांग्रेस ने हिंदी माध्यम के बच्चों तक के भविष्य की चिंता नहीं की।

मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को हमारे बच्चों की चिंता होती तो स्कूलों में बच्चों का आधार मजबूत करने का काम करती और पहली कक्षा से अंग्रेजी का बेस मजबूत करती। अंग्रेजी अध्ययन के लिए ग्रामर और शब्दावली की आवश्यकता होती है लेकिन कांग्रेस ने बच्चों का ग्राउंड तैयार नहीं किया, बिना बेस के बच्चे सीधे हिंदी माध्यम विद्यालयों को

> ■ 'कांग्रेस ने ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया, ना ही शिक्षकों की नियुक्ति की, वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए'

अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। ऐसे में हिंदी माध्यम में पढ़ने वाला बच्चा जब अंग्रेजी पुस्तके अध्ययन नहीं कर पाएगा तो निराश ही होगा। हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करना कांग्रेस का अव्यवहारिक फैसला था।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने बिना चिंतन-मनन किए आनन-फानन में ऐसा फैसला कर दिया जो पूर्णतया अप्रासांगिक था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसे परिस्थिति को देखते हुए समीक्षा कमेटी का गठन किया है। कमेटी में यह तय किया जाएगा कि बच्चों का ग्राउंड कैसे मजबूत किया जाए और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य व्यवस्थाएं कैसे मजबूत की जाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने महज एक साल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। भाजपा सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं के प्रवेश के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की, 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, 12 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में क्रमोन्नयन किया। सरकार ने 89 हजार विद्यार्थियों को टेबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन वितरित किए, 8.51 लाख साइकिल वितरित की, एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 514 करोड़ रूपए व्यय किए। इससे 2 लाख 50 हजार 415 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा पहले ये बताएं कि अंग्रेजी स्कूल कांग्रेस ने खोले थे क्या। कांग्रेस से बड़ा झूठ कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हिन्दी माध्यम स्कूलों के ऊपर केवल अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाएं थे। उसमें ना कोई अंग्रेजी माध्यम के टीचर थे, ना कोई वहां भवन था और ना कोई परिसर थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल लूट-पाट का दरवाजा खोला था। कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी स्कूलों में अध्यापक दिए ही नहीं। हिन्दी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएं एवं हिन्दी वाले स्कूल इसलिए पिछड़ गए कि उनके पास अध्यापक नहीं थे, तो इससे अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ और हिन्दी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ। इस अन्याय के लिए भगवान कांग्रेस को किसी भी तरह से माफ नहीं करेंगा। उन्होंने कहा कि डोटासरा आजकल अपने परिवार वाले की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहले रोज जो चोरी का पैसा लाते थे वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल-कूद कर रहे हैं। डोटासरा की स्थिति बिना पानी के तड़पती हुई मछली के जैसी है।

'अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे'

जयपुर। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में खोले गये 3737 महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा के लिये मंत्रिमण्डलीय समिति क्यों गठित की गई, सालभर तक सरकार क्यों सोती रही, इसका जवाब प्रदेश की जनता मांग रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रदेश में 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं और इस वर्ष 677000 से अधिक छात्र-छात्रायें प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले अधिक है। इन सभी छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निःशुल्क मिल रही है और पिछले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 709270 से थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में इन स्कूलों के लिये 45300 पद स्वीकृत किये गये थे, अलग से अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षकों का कैडर बनाया गया था तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा दस हजार नई भर्तियां भी की गई थी एवं इन्टव्यू व परीक्षा लेकर इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक लगाने का कार्य किया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा शासन में पिछले एक वर्ष से इन स्कूलों में 17192 पद रिक्त हैं, इनमें शिक्षकों के 13552 तथा क्लेरिकल स्टॉफ के 3440 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिये मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री ने एक भी भर्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने परीक्षा करवाकर भर्ती करने का केवल स्वांग किया।

उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिये गठित कमेटी का संयोजक उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है, पूर्व में भी यह जिलों की समीक्षा हेतु गठित कमेटी में थे, किन्तु समीक्षा कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही इन्हें उस कमेटी से हटा दिया गया था और इन्हीं का जिला निरस्त हो गया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री को वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के लिये गठित कमेटी से बीच में ही हटना पड़ेगा क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र में 59 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

चिकित्सा मंत्री ने की जनसुनवाई

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने शनिवार को अपने राजकीय आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं।

जयपुर । चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने शनिवार को अपने राजकीय आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं और इनका तत्काल प्रभाव से यथोचित निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खींवसर, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से आत्मीयता के साथ मिले और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के संबंध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याणकारी सोच के साथ एक से बढ़कर एक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आमजन का जीवन स्तर बेहतर हो और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कर राहत पहुंचाई जाए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आमजन को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। विगत अल्प समय में ही गांव-ढाणी तक चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। करीब 21 हजार पदों पर विभाग में नियुक्तियां दी गई हैं और शेष रिक्त पदों के लिए भी संकल्पबद्ध होकर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक भी आमजन सुगमता के साथ जांच और उपचार प्राप्त कर सकें। लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच इन शिविरों के माध्यम से की जा रही हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खींवसर ने जनसुनवाई के दौरान समस्याएं सुनने के साथ ही आमजन से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लें और आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करने के पवित्र उद्देश्य में सहभागी बनें।

आमजन के सुझावों से तैयार होगा विकासोन्मुखी और जनहितैषी बजट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को केन्द्र बिन्दु मानकर आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी, गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी बजट पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं।

> ■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16 जनवरी से हितधारकों के साथ करेंगे बजट पूर्व चर्चा

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित होने वाली बजट पूर्व बैठकों में चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को कर्मचारी संघों, 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र, 20 जनवरी को उद्योग एवं सेवा तथा कर सलाहकारों, व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव हेतु चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार 21 जनवरी को युवा व खेल क्षेत्र तथा महिला प्रतिनिधियों व प्रतिभाशाली छात्र, 22 जनवरी को किसान, पशुपालक व डेयरी संगठनों तथा एनजीओ व उपभोक्ता फोरम आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि आगामी बजट हेतु वित्त विभाग की वेबसाइट पर 10 जनवरी तक सुझाव ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक हितधारकों एवं विभिन्न वर्गों द्वारा 75 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।

जोधपुर देहात में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति

जोधपुर/जयपुर। भाजपा ने जोधपुर देहात में अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए 13 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। यह घोषणा जोधपुर जिला प्रभारी रामचरण बोहरा द्वारा की गई। पार्टी ने इन नियुक्तियों के जरिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को विस्तार देने की रणनीति अपनाई है। भाजपा देहात दक्षिण जिला मंत्री,जिला मीडिया सयोजक रमेश बिश्नोई ने बताया कि जोधपुर जिला प्रभारी रामचरण बोहरा ने कहा कि सभी नियुक्तियां संगठनात्मक मजबूती और अनुभव को ध्यान में रखकर की गई हैं। उन्होंने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को बधाई देते हुए आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करेंगे और जनता से जुड़ाव बढ़ाएंगे। नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के नाम सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं हो : जस्टिस गवई

जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं हो, यह हमारा पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में विधिक सेवा प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रदेश की विधिक सेवा में एक नया आयाम जुडा है और इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। जस्टिस गवई शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नव निर्मित भवन के शुभारंभ के बाद जेल सुधार को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का नया भवन हेरिटेज के साथ-साथ हाईटेक भी है। जस्टिस गवई ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा देने के लिए स्कूल खोली, आज उनके सम्मान में देशभर के बच्चों के लिए शॉर्ट फिल्म की प्रतियोगिता तैयार की गई।

> ■ जस्टिस गवई ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नव निर्मित भवन के शुभारंभ के बाद जेल सुधार को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया

सेमिनार को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने कहा कि जेल में रखकर किसी का सुधार नहीं किया जा सकता। पैरोल की सुविधा से कैदी अपने परिवार से मिल सकता है। वहीं आपात पैरोल में भी कई बार देरी हो जाती है। प्रदेश में ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर में काम किया जा रहा है। वहीं जेल में जाति आधारित कार्य वितरण को भी समाप्त किया गया है। जस्टिस मेहता ने जेल नियमों में बदलाव की आवश्यकता जताते हुए कहा कि खुली जेलों की संख्या बढाने से कई समस्याएं खत्म हो जाएगी और इसमें नियमित जेलों के मुकाबले खर्चा भी काफी कम होता है। जस्टिस मेहता ने कैदियों को श्रम के बदले प्रतिदिन 112 रुपए देने के सिस्टम को सुधारने की दिशा में भी राज्य सरकार को ध्यान देने को कहा है। कार्यक्रम में 6 से 18 साल के विशेष योग्जन बच्चों को दो साल के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने की शुरूआत की गई। वहीं रालसा के नए लोगो का भी अनावरण किया गया। इसके अलावा अधिकार मित्रों को बैजेज का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज जसराज चोपडा की ओर से विधिक कार्यो के लिए दी गई बडी धनराशि देने पर उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में सीजे एमएम श्रीवास्तव सहित हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे।

भांकरोटा सड़क दुर्घटना प्रकरण में मृतक आश्रितों और घायलों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी

जयपुर। दिल्ली-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के समीप 20 दिसंबर को घटित दुर्घटना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए दुर्घटना के 20 मृतकों के आश्रितों एवं 24 घायल व्यक्तियों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित कर दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा 20 मृतक आश्रितों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक करोड़ रुपये (प्रति मृतक आश्रित 5-5 लाख) राशि हस्तांतरित कर दी गई है एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देय 1 करोड़ 20 लाख रुपये (प्रति मृतक आश्रित 6-6 लाख) की मुआवजा राशि हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बीमित 11 मृतकों के आश्रितों के बैंक के खाते में योजना के तहत 55 लाख रुपये (प्रति मृतक आश्रित 5-5 लाख) की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई है।

वहीं, दुर्घटना में घायल 24 व्यक्तियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 24 लाख रुपये (प्रति घायल1-1 लाख) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देय 48 लाख रुपये (प्रति घायल 2-2 लाख) की मुआवजा राशि हस्तांतरित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राहत कोष से प्रति मृतक राशि 2 लाख एवं प्रति घायल राशि 50 हजार की आर्थिक सहायता हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

नए नियमों से खनिज सेक्टर को मिलेगा बूस्टअप, प्रक्रिया सरल होगी

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसेण्ड नीति 2024 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश में नई खनिज नीति लागू करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में 4 दिसबंर में नई खनिज और एम-सेण्ड नीति जारी करने के साथ ही अब राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमों में भी नई नीतियों के अनुरुप आवश्यक प्रावधान किये गए है। राज्य की नई खनिज नीति व अब नियमों में प्रावधानों से खनिजों के खोज कार्य में तेजी लाने, खनिज रियायतों का समय पर आवंटन, खनन क्षेत्रों के विकास, खनिज बजरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित

> ■ राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 2017 में संशोधन अधिसूचना जारी

करने, खनन नियमों व परमिट व्यवस्था सहित प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने, अवैध खनन, निगर्मन व भण्डारण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति अपनाने, खनन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग सहित प्रदेश में खनिज क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ाने की राह प्रशस्त हो गई है। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 2017 में आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार समस्त रॉयल्टी पेड खनिजों के परिवहन में लागू ई-टी.पी. की व्यवस्था को ई-वे बिल के परिप्रेक्ष्य में खनिज बजरी, मेसेनरी स्टोन की गिट्टी/ग्रिट/क्रशर डस्ट/एम-सेण्ड तक सीमित किया गया है। स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के वर्तमान प्रावधान से सम्भावित राजस्व हानि देखते हुए इसे समाप्त कर गैप क्षेत्र के आवंटन में रिजर्व प्राईस डेड रेन्ट/लाईसेंस फीस को 10 गुणा से बढाकर 25 गुणा किया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने हेतु खनन पट्टा आवंटित करने की गाईडलाईन जारी की जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार जनजाति क्षेत्र में अप्रधान खनिज की रियायतों की नीलामी में स्थानीय निवासियों की भागीदारी के लिए बिड सिक्योरिटी 10 लाख से घटाकर 5 लाख तथा खनिज रियायतों के प्लॉट्स की नीलामी में फर्जी बिड रोकने हेतु 30 करोड से अधिक की बोली पर बिड सिक्योरिटी की राशि, प्रस्तुत बिड राशि की 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं होने पर रेरा को शिकायत सुनने का अधिकार

जयपुर। राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक मामले में कहा है कि प्रोजेक्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र ना होने पर रेरा को आवंटियों की शिकायत सुनने और उन्हें राहत दिए जाने का अधिकार है। प्रोजेक्ट के कुछ प्लाट्स पर जेडीए की ओर से पट्टे दिए जाने मात्र से निर्माणशुदा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन की पालना करने से नहीं बच सकते। प्राधिकरण सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने यह आदेश आवंटी दामोदर लाल सैनी व अन्य की शिकायतों पर निर्णय देते हुए दिए।

आवंटी के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि आंवटी ने साल 2014 में यूनिक सिटी में एक विला बुक कराया था। बिल्डर ने उसे आश्वस्त किया था कि संपूर्ण योजना को पूरा कर आवंटी को साल 2020 तक विला का कब्जा दे दिया जाएगा। इसके बावजूद भी बिल्डर ने योजना को विकसित नहीं किया और विला का कब्जा भी नहीं सौंपा। इस पर आवंटी ने साल 2022 में रेरा में अपनी शिकायत दी। जिसके जवाब में बिल्डर ने कहा कि प्रोजेक्ट रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए शिकायत को खारिज किया जाए। बिल्डर ने कहा कि रेरा नियम के नियम 4 के अनुसार यदि संबंधित निकाय की ओर से टाउनशिप योजना के प्लाट्स के आवंटन पत्र या पट्टे जारी करना शुरू किया गया तो ऐसा योजना रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। बिल्डर की ओर से यह भी बताया गया कि यूनिक सिटी योजना 2 फेज में निर्मित की जानी थी। फेज 1 रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए आवंटी रेरा से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा प्राधिकरण ने फैसला देते हुए माना की यदि किसी योजना के संदर्भ में सक्षम संस्था द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो ऐसी योजना रेरा के क्षेत्राधिकार में आती है। बिल्डर ने आवंटी को यह नहीं बताया था कि टाउनशिप 2 फेज में बनाई जा रही है। आवंटी को संपूर्ण योजना एक ही होना बताकर विला बेचा गया था। इसके अलावा नियम 4 में दी गई छूट भी प्लाट के संबंध में है, ना की विला के संबंध में। इसके साथ ही रेरा ने आवंटी की ओर से अदा की गई संपूर्ण राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश देते हुए यूनिक सिटी फेज 1 को रेरा के समक्ष पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।

योग और व्यायाम अपनाने का आव्हान किया राज्यपाल ने

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को छत्रपति संभाजी नगर में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार और विद्यालयी छात्र-छात्राओं को महापुरुषों के जीवन से सीख लेने का आव्हान किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को छत्रपति संभाजी नगर में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार और विद्यालयी छात्र छात्राओं को महापुरुषों के जीवन से सिख लेने का आव्हान किया।

बागडे ने शनिवार को स्थानीय गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने वहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय जनों को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य सुविधाओं से लाभांवित किए जाने का आव्हान किया। निधोना गांव में राज्यपाल ने प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन कर शिक्षा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहां उन्होंने छात्र-छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद भी किया। इसी तरह बिधूना गांव में चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने एंबुलेंस का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत को एंबुलेंस की चाबियां सौंपते हुए उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल बागडे का विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने भावभरा अभिनन्दन करते हुए उनके सार्वजनिक सरोकारों और आम जन के लिए समर्पित जीवन की सराहना की।

ओपन जेल में अस्पताल बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश

जयपुर। सांगानेर स्थित देश की पहली ओपन जेल की जमीन पर हॉस्पिटल बनाए जाने के मामले में कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमिश्नर की रिपोर्ट में मुख्य तौर पर कैदियों के कल्याण व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों पर जोर दिया है। इसके अलावा जेल की मौजूदा संरचनाओं को परिसर के भीतर वैकल्पिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की गई है, ताकि 300 बैड्स के सेटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण जेल की कार्यक्षमता से समझौता किए बिना ही किया जा सके। कमिश्नर की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आगामी सुनवाई पर विचार करेगा।

रिपोर्ट के साथ नक्शा पेश कर कहा कि लाल चिह्नित क्षेत्र में स्थित मौजूदा कैदी सुविधाओं को नीले और हरे चिह्नित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे कि जेल की संचालन प्रक्रिया सुचारू तौर पर जारी रह सके। इस स्थानांतरण योजना से कैदियों के लिए बेहतर आवास व सामुदायिक जगह बनाई जा सकेगी और इससे उनके जीवन को भी सुधारा जा सकेगा। इस दौरान स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कैदियों के कल्याण व अधिकारों से किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

राजरंगम् के मंच पर साकार हुई अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी

जयपुर। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7वें राजरंगम् का तीसरा दिन गुरुदेव रबीन्द्र नाथ टैगोर की कहानी पर आधारित नाटक चित्रांगदा के नाम रहा। शनिवार को संकेत जैन के निर्देशन में हुई प्रस्तुति में कलाकारों ने अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी को बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हुए वास्तविक सुंदरता को अपनाने का संदेश दिया गया। रविवार को शाम 6:30 बजे सुनीता तिवारी नागपाल (एनएसडी) के निर्देशन में पीले स्कूटर वाला आदमी नाटक का मंचन होगा।

चित्रांगदर की कहानी, महाभारत के एक प्रसंग से प्रेरित है। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन के प्रति बेहद आकर्षित है, लेकिन उसका हृदय जीतने में असफल रहती है क्योंकि उसमें कामुक सुंदरता की कमी है और सामान्य जीवन में वह एक निडर पुरुष की तरह व्यवहार करती है। चित्रांगदा के अनुरोध पर, प्रेम के देवता, कामदेव, उसे एक वर्ष के लिए शारीरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं, और परिणामस्वरूप अर्जुन उससे प्रसन्न होता है। तब उसकी पहिरन उसे ज्ञात नहीं थी। हालांकि वर्ष समाप्त होने से पहले, अर्जुन उससे विमुख होने लगता है, और योद्धा राजकुमारी के पराक्रम की सूचना से उसके मन में उसके लिए गहरी प्रशंसा पैदा हो जाती है। तब चित्रांगदा अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है, और वह उससे और भी अधिक प्यार करने लगता है, और नाटक खुशी से समाप्त हो जाता है। नाटक प्रतीकात्मक रूप से शारीरिक सुख और कामुक संतुष्टि से परे, वास्तविक सुंदरतस की व्याख्या और अन्वेषण करता है। इस काव्यात्मक नाटक को काव्यात्मक बिंबों, प्रतीकों और अत्यंत सुंदर भावों के कारण संचार के लिए एक नई नाट्यय भाषा की आवश्यकता है। निर्देशक ने विशिष्ट वेशभूषा और लाइट के प्रभाव के जरिए प्रकृति के सौंदर्य का बखूबी चित्रण किया। इसी के साथ संवादों में भाषा का लालित्य भी स्पष्ट रूप से साकार हुआ। शृंगार रस से ओत प्रोत यह प्रस्तुति मानव हृदय में प्रेम भावों को सहज रूप से उत्पन्न करती है।

गरीमा पारीक ने चित्रांगदा, विक्रांत रतनपाल ने अर्जुन, विमल मीणा ने कामदेव, आकर्ष काला ने बसंत, पीयूष सैन ने वनचर की भूमिका निभाई। अन्य कलाकारों में दिव्यांशी, सिमरन, आयुषी एवं इशिका शामिल रही। बादशाह जहानी और बरकत जहानी ने संगीत संयोजन, सुनीता बर्मन ने वेशभूषा, संकेत जैन व गौरव ने प्रकाश संयोजन, गगन त्रिवेदी ने मंच सज्जा और धनंजय ने मंच सहायक की जिम्मेदारी संभाली।